RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 02 JUNE TO 08 JUNE 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 41 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

आठ बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में अप्रैल में 56.1 प्रतिशत की वृद्धि Page 4

किराए पर घर लेना और देना होगा आसान मॉडल टेनेंसी एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी Page 5

सेफ्टी टेस्टः 'देसी' कारों ने छुड़ाए विदेशी कंपनियों के छक्के, टॉप 5 पर भारत का कब्जा Page 7

editoria!

बच्चों को राहत

महामारी ने हजारों परिवारों का आसरा छीन लिया है और बड़ी संख्या में बच्चे बेसहारा हो गये हैं. ऐसे बच्चों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जिं बच्चों के माता-पिता को आपदा ने छीन लिया है, उन्हें 18 साल की आयु तक एक निर्धारित वृत्ति मिलेगी और 18 से 23 साल की अवधि में उच्च शिक्षा व अन्य आवश्यकताओं के लिए पीएम-केयर्स के तहत 10 लाख रुपये कोष के माध्यम से सहायता मिलेगी. ऐसे बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जायेगा. मृत व्यक्ति की आमदनी के अनुरूप आश्रित परिवार को पेंशन देने का प्रस्ताव है तथा बीमा सीमा को भी बढ़ाया जा रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल और 25 मई के बीच 577 बच्चे अनाथ हुए हैं. वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रेडियो संबोधन में भी देश को आश्वस्त किया है कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. बच्चे ही भारत के सुखी और समृद्ध भविष्य की नींव हैं. जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है, उनके सामने पहाड़-सा अनिश्चित जीवन है. यदि उन्हें इस समय सहारा नहीं मिलेगा, तो न वे ठीक से शिक्षित हो सकेंगे और न ही अपने और अपने परिवार के लिए बाद में कुछ कर सकने की स्थिति में होंगे. इस वंचना से बचाने के लिए सरकार का आगे आना आवश्यक और सराहनीय पहल है. शिक्षा के व्यय और विद्यालयों की व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के लिए बीमा की सुविधा से बच्चों को अपना भविष्य संवारने का अवसर प्राप्त होगा. परिवार के लिए पेंशन और बीमा से संबंधित सुविधाओं से परिवार का दबाव भी कम होगा तथा सभी सदस्य नये सिरे से जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकेंगे. इस घोषणाओं पर अमल भी शुरू हो गया है. केंद्रीय श्रम आयुक्त राज्यों से कोरोना का शिकार हुए कामगारों की जानकारी जुटा रहे हैं. उल्लेखनीय है कि अनेक राज्य सरकारों ने भी प्रभावित गरीब और निम्न आय वर्ग के बच्चों व परिवारों को राहत देने की घोषणा की है. आगामी दिनों में ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ने की आशा है. बीते सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्यों से बच्चों की देखभाल का निर्देश दिया है तथा प्रभावित बच्चों के बारे में सूचनाओं को राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है. न्यायालय ने महामारी और लॉकडाउन से पैदा हुई स्थिति में बच्चों को भोजन, वस्त्र और आश्रय आदि तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने का आदेश पहले ही जारी किया है. उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रभावित परिवारों और बच्चों को सहायता देने की घोषणाओं को पूरा करने का हरसंभव प्रयास करेंगी. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रयास में एक भी जरूरतमंद बच्चा पीछे नहीं छूटे.

कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएगा ओपेक

क्या घटेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें

फ्रैंकफर्ट। एजेंसी

तेल निर्यात देशों के संगठन (OPEC) और सहयोगी उत्पादक देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। वे तेल उत्पादन बढ़ाकर 21 लाख बैरल प्रतिदिन करेंगे। कुछ देशों में इकोनॉमिक रिकवरी (Economic recovery) को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। ओपेक और सहयोगी तेल उत्पादक देशों (OPEC Plus) के ऊर्जा मंत्रियों की मंगलवार को 'ऑनलाइन' बैठक में यह निर्णय किया है। कच्चे तेल (Crude Oil) का उत्पादन बढ़ने से इसकी कीमतों में कमी आने के आसार हैं। अभी कच्चे तेल की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल है। मंगलवार को वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) का भाव 2.2 प्रतिशत बढ़कर 70.85 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटती है तो इसका असर घरेलू बाजार में पेट्रोल (petrol) और डीजल (diesel) की कीमतों पर पड़ सकता है। इनकी कीमतों में कमी आ सकती है। अभी देश के कुछ जगहों में पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। ओपेक (OPEC) और संबद्ध उत्पादक देशों के सदस्य वैश्विक तेल बाजारों में परस्पर विरोधी दबावों से जूझ रहे हैं। एक तरफ जहां भारत जैसे कुछ देशों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण मांग कम होने का अंदेशा है, जबकि कुछ देशों में आर्थिक पुनरूद्धार हो रहा है जिससे मांग बढ़ने की उम्मीद है। सऊदी अरब की अगुवाई में ओपेक तथा अन्य सहयोगी

देशों को इस बात की चिंता है कि भारत जैसे देशों में कोविड-19 (Covid-19) महामारी फैलने से वैश्विक मांग और कीमतों पर असर पड़ेगा। भारत प्रमुख तेल उपभोक्ता बाजार है। तेल उत्पादक देशों (Oil producing countries) ने 2020 में महामारी के कारण आयी नरमी को देखते हुए कीमतों को समर्थन देने के इरादे से उत्पादन में उल्लेखनीय कटौती की थी और अब उन्हें इस बात का निर्णय करना था कि तेल उत्पादन बढ़ाना बाजार के लिये कितना जरूरी है। अमेरिका, यूरोप ओर एशिया में आर्थिक पुनरूद्धार से दूसरी छमाही में ऊर्जा मांग बढ़ने की उम्मीद है।

'समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद उसमें शामिल नहीं रहे दावे निरस्त माने जाएंगे'

नई दिल्ली। एजेंसी

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कहा है कि कर्ज में डूबी किसी भी कंपनी के लिये समाधान योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद जो दावे योजना का हिस्सा नहीं थे, वो निरस्त माने जाते हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण की चेन्नई पीठ ने कहा कि यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण सहित सभी सांविधिक निकायों के दावों पर भी लागू होता है।

न्यायाधिकरण ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की याचिका खारिज करते हुए कहा, ''कोई भी व्यक्ति ऐसे दावे के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही जारी रखने का हकदार नहीं होगा जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है।''

पीठ के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने 13 अप्रैल, 2021 को घनश्याम मिश्रा एंड संस के मामले में दिए गए एक फैसले में कहा है कि एक बार जब समाधान योजना को एनसीएलटी द्वारा विधिवत मंजूरी दे दी जाती है, तो सभी दावे समाप्त हो जाते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि ऐसे सभी दावे, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी दावे के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का हकदार नहीं होगा, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है।

एनसीएलएटी ने कहा, ''माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून के आधार पर यह स्पष्ट है कि धारा 31 के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के बाद जो भी दावे हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। और वह केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण, गारंटर और अन्य हितधारकों सहित कर्मचारी, सदस्य तथा अन्य पक्षों पर लागू होते हैं।'' अपीलीय न्यायाधिकरण का यह निर्देश कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तेलंगाना के क्षेत्रीय आयुक्त की याचिका पर आया।

आयुक्त ने एनसीएलटी चेन्नई के एक आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि 20 जुलाई, 2020 को जीवीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की समाधान योजना को मंजूरी देते हुए न्यायाधिकरण ने कंपनी पर बकाया भविष्य निधि के एक बड़े हिस्से को माफ कर दिया था। जीवीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने अप्रैल 2014 से कर्मचारियों के अंशदान सहित बकाया/नुकसान/ब्याज के भुगतान में चूक की थी। जबकि कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन से योगदान राशि को काट लिया गया था। अब तक का कुल ईपीएफ बकाया 2.84 करोड़ रुपये है। हालांकि, जीवीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के समाधान पेशेवर ने सूचित किया था कि संभावित बोलीदाता के अधिग्रहण के समय 1.95 करोड़ के दावों का भुगतान स्वीकार किया जाएगा। समाधान पेशेवर ने कहा था कि पहले से स्वीकृत दावे का समाधान योजना के तहत निपटारा किया जाएगा। हालांकि, ईपीएफओ ने 2.84 करोड़ का दावा किया था और एनसीएलएटी में याचिका दायर की थी।

कोल इंडिया की कोयला आपूर्ति मई में 38 प्रतिशत बढ़कर 5.5 करोड़ टन पर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की कोयला आपूर्ति मई में 38 प्रतिशत बढ़कर 5.5 करोड़ टन पर पहुंच गयी। बिजली क्षेत्र की मांग में सुधार से कोल इंडिया की आपूर्ति बढ़ी है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा, ''बिजली क्षेत्र की कोयले की मांग सुधरने से कोल इंडिया ने किसी भी साल के मई माह के लिए अब तक सबसे अधिक 5.5 करोड़ टन का उठाव (आपूर्ति) का आंकड़ा दर्ज किया है। यदि कोविड-19 से पहले से तुलना की जाए, तो भी मई का उठाव का आंकड़ा 5.8 प्रतिशत बेहतर है। मई, 2019 में कोयले का उठाव 5.2 करोड़ टन रहा था। मई में बिजली क्षेत्र को कोल इंडिया की आपूर्ति 41 प्रतिशत बढ़कर 4.4 करोड़ टन पर पहुंच गई। पिछले साल मई की तुलना में कोल इंडिया ने बिजली क्षेत्र को 1.3 करोड़ टन की अधिक आपूर्ति की है। चालू वित्त वर्ष के पहले दो माह अप्रैल-मई में कोल इंडिया की कुल कोयला आपूर्ति 10.92 करोड़ टन रही, जो इससे पिछले साल की समान अवधि के 7.9 करोड़ टन से 38 प्रतिशत अधिक है।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे टूटा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

विदेशी बाजारों में डॉलर के मजबूत होने और घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुख के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार में बुधवार को रुपये में लगातर तीसरे दिन गिरावट जारी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे और टूटकर 73.09 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया कमजोर रुख के साथ 73.13 प्रति डॉलर पर खुला जो इससे पूर्व 72.90 रुपये पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 73.04 से 73.30 रुपये प्रति डॉलर के दायरे में रहा। अंत में यह 73.09 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विगत तीन कारोबारी सत्रों में रुपया 64 पैसे नीचे आ चुका है। इस बीच, छह मुद्राओं की तुलना में डॉलर का रुख दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.35 प्रतिशत बढ़कर 90.14 पर पहुंच गया। बीएसई में 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 85.40 अंक की गिरावट के साथ 51,849.48 अंक रह गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा भाव 1.12 प्रतिशत बढ़कर 71.04 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

फिक्की ने आर्थिक गतिविधियों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने, निगरानी जारी रखने का सुझाव दिया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में कोरोना वायरस मामलों में कमी आने के बीच उद्योग मंडल फिक्की ने सरकार को आर्थिक गतिविधियों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने तथा साथ ही निगरानी बनाये रखने का सुझाव दिया है। फिक्की के अनुसार अगर कोई इकाई कोविड से बचाव के नियमों का पालन करते हुए पूरी तरह से अलग-थलग होकर (आइसोलेशन बबल) परिचालन करने में सक्षम है, तो उसे हर समय काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। भले ही वह जरूरी सेवाओं और उत्पादो के दायरे में नहीं आती हो।

उद्योग मंडल ने कहा कि दूसरी लहर की गति ने रेखांकित किया है कि प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करने से मामलों में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ सकता है। फिक्की ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में कहा, ''पहली और दूसरी लहर से सीख लेते हुए हमारा सुझाव है कि आर्थिक गतिविधियों को अनुमति देने के लिये चरणबद्ध रुख अपनाया जाए। यह जीवन और आजीविका को संतुलित करता है।''

सुझाव में कहा गया है कि अगर मामले तेजी से कम भी होते हैं, तो भी निगरानी के तौर पर परीक्षण जारी रहना चाहिए। फिक्की ने उदाहरण देते हुए कहा कि हवाईअड्डा, रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों पर लोगों का औचक परीक्षण होते रहना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जिन इकाइयों ने एक खुराक के साथ कम-से-कम अपने 60 प्रतिशत कर्मचारियों का टीकाकरण करवा लिया है, उन्हें प्रतिबंधों से छूट दी जा सकती है। उद्योग मंडल के अनुसार संपर्क से जुड़े गैर-जरूरी क्षेत्रों जैसे छुट्टियां बिताने से संबंधित गतिविधियों, खुदरा आदि क्षेत्रों में अनुमति तभी मिले जब संक्रमण की दर 2.5 प्रतिशत से नीचे हो यानी जोखिम की स्थिति न्यूनतम हो। फिक्की के अनुसार, ''जब तक देश की ज्यादातर आबादी कम-से-कम टीके की एक खुराक न ले ले, पाबंदियां जारी रहनी चाहिए।''

रिजर्व बैंक की बैठक शुरू, होगा नीतिगत दरों में बदलाव?

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

बैंकिंग क्षेत्र के नियामक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक बुधवार को शुरू हुई। देश के जो वर्तमान हालात हैं, उसे देखते हुए एमपीसी की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। समझा जा रहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर (2nd Wave of Corona) के प्रकोप के चलते पैदा हुई अनिश्चितता के कारण नीतिगत दरों में यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला हो सकता है।

महंगाई का असर ब्याज दरों पर?

इस समय महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। इसलिए मुद्रास्फीति में तेजी की आशंका के चलते एमपीसी से ब्याज दरों में किसी बदलाव की उम्मीद कम है। हर दो महीने के अंतराल पर होने वाली इस मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। आरबीआई ने अप्रैल में हुई पिछली एमपीसी बैठक में प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। इस समय रेपो दर चार प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर है।

जीडीपी के आंकड़ों से राहत

ब्रिकवर्क रेटिंग्स के मुख्य आर्थिक सलाहकार एम गोविंदा राव ने कहा है कि उम्मीद से बेहतर जीडीपी के आंकड़ों से एमपीसी को वृद्धि के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि हालांकि देश के कई हिस्सों में लगाए गए आंशिक लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों के चलते वृद्धि को लेकर नकारात्मक जोखिम तेज हो गए हैं। ऐसे में संभावना है कि आरबीआई अपने उदार मौद्रिक नीति रुख को जारी रखेगा और सतर्क दृष्टिकोण के साथ रेपो दर को चार प्रतिशत पर बनाए रखेगा।

उदार रूख रह सकता है बरकरार

हाउसिंग डॉट कॉम के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाल का मानना है कि आरबीआई मुद्रास्फीति को काबू में रखने के अपने प्रमुख लक्ष्य को खतरे में डाले बिना अपने उदार रुख को बनाए रख सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के समूह अध्यक्ष (उपभोक्ता बैंकिंग) शांति एकंबरम ने भी कहा कि एमपीसी नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखेगा और एक उदार रुख के साथ प्रणाली में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा।

भारत को पीछे छोड़ 2021 में स्टेनलेस स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन सकता है इंडोनेशिया

नयी दिल्ली। एजेंसी

उद्योग संगठन इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईएसएसडीए) ने मंगलवार को कहा कि इंडोनेशिया भारत को पीछे छोड़ 2021 में स्टेनलेस स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन बन सकता है। आईएसएसडीए ने एक बयान में यह भी कहा कि इंडोनेशिया का अधिशेष उत्पादन भारतीय बाजार में भेजा जा सकता है। पिछले हफ्ते डिजिटल तरीके से हुए इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील फोरम (आईएसएसएफ) के वार्षिक सम्मेलन में पेश किए गए अनुमानों के मुताबिक इंडोनेशिया कैलेंडर वर्ष 2021 में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टेनलेस स्टील उत्पादक तौर पर भारत की जगह ले सकता है। आईएसएसडीए ने कहा कि इस समय वैश्विक स्टेनलेस स्टील उत्पादन में चौथे स्थान पर मौजूद इंडोनेशिया 42 लाख टन के कुल उत्पादन के साथ जापान और भारत को पीछे छोड़ सकता है। संगठन ने कहा कि इस साल भारत के 35 लाख टन स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने का अनुमान है। पिछले साल यह 32 लाख टन था। आईएसएसडीए ने कहा कि चीनी स्टेनलेस स्टील कंपनियों द्वारा इंडोनेशिया में स्थापित किए गए भारी क्षमताओं वाले संयंत्रों के इस साल काम शुरू करने की उम्मीद है और उसके साथ होने वाला अधिशेष उत्पादन भारतीय बाजारों में भेजा जा सकता है। संगठन के अध्यक्ष के के पाहुजा ने कहा कि चीनी सरकार ने मई 2021 में निर्यात कर छूट वापस ले ली थी जो चीन से स्टेनलेस स्टील के निर्यात पर रोक लगाता है। चीनी कंपनियां इस वजह से इंडोनेशिया में बड़े संयंत्र स्थापित कर रही हैं।

मई में निर्यात 67 प्रतिशत बढ़कर 32.21 अरब डॉलर पर पहुंचा, व्यापार घाटा 6.32 अरब डॉलर रहा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का निर्यात मई में 67.39 प्रतिशत बढ़कर 32.21 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम उत्पादों और रत्न एवं आभूषण के निर्यात में खासतौर से तेजी देखी गई। हालांकि, इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 6.32 अरब डालर पर पहुंच गया। मई 2020 में निर्यात 19.24 अरब अमेरिकी डॉलर और मई 2019 में यह 29.85 अरब अमेरिकी डालर रहा था। बयान के मुताबिक मई 2021 में आयात में भी अच्छी वृद्धि हुई और यह 68.54 प्रतिशत बढ़कर 38.53 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो मई 2020 में 22.86 अरब डॉलर और मई 2019 में 46.68 अरब डॉलर रहा था। मंत्रालय ने कहा, ''भारत इस तरह मई 2021 में 6.32 अरब अमेरिकी डालर के व्यापार घाटे के साथ शुद्ध आयातक रहा है। मई 2020 में व्यापार घाटा 3.62 अरब डॉलर था। व्यापार घाटे में मई 2020 के मुकाबले 74.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं मई 2019 के व्यापार घाटे 16.84 अरब डालर के मुकाबले इसमें 62.49 प्रतिशत की गिरावट आई है।'' समीक्षाधीन महीने में तेल आयात बढ़कर 9.45 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि मई 2020 में यह 3.57 अरब अमेरिकी डॉलर था। मई 2019 में 12.59 अरब डालर का पेट्रोलियम पदार्थों का आयात हुआ था। इस साल अप्रैल-मई के दो महीनों के दौरान निर्यात बढ़कर 62.84 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 29.6 अरब डॉलर और अप्रैल-मई 2019 में 55.88 अरब डॉलर रहा था। अप्रैल-मई 2021 के दौरान आयात 84.25 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो अप्रैल-मई 2020 में 39.98 अरब डॉलर और अप्रैल-मई 2019 में 89.07 अरब डॉलर था। विदेश व्यापार आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (टीपीसीआई) के संस्थापक अध्यक्ष मोहित सिंगला ने कहा कि अखबारी कागज, परिवहन उपकरण और लोहा तथा इस्पात के आयात में गिरावट आना आत्मनिर्भरता की दिशा में स्वागत योग्य कदम है और इससे पता चलता है कि इस दिशा में सरकार की रणनीति कारगर रही है। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) ने कहा कि पिछले साल इसी महीने सख्त लॉकडाउन के कारण मई 2021 के लिए आधार प्रभाव कम होने के चलते साल-दर-साल बढ़ोतरी देखने को मिली है। परिषद ने उम्मीद जताई कि अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में मजबूत मांग के चलते वित्त वर्ष में निर्यातकों की ऑर्डर बुक मजबूत बनी रहेगी।

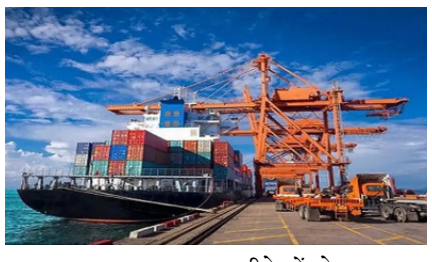

कोविड-19 प्रकोपः एसोचैम ने उद्योगों के लिए वेतन समर्थन, ब्याज सब्सिडी की मांग की

नयी दिल्ली। एजेंसी

उद्योग मंडल एसोचैम ने बुधवार को सरकार से कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रकोप का सामना कर रहे एमएसएमई के लिए नियामकीय सहूलियतों, वेतन समर्थन और ब्याज सब्सिडी जैसे राहत उपायों की सिफारिश की। एसोचैम ने कहा कि इस समय राज्य लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं और ऐसे में व्यापार तथा उद्योगों को चौतरफा सहयोग की जरूरत होगी। उद्योग संगठन ने सुझाव दिया कि ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के अधिशेष धन का उपयोग कर्मचारियों के लिए वेतन सहायता उपायों और प्रोत्साहन पैकेज देने के लिए किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों में कहा गया है, ''यह वित्तीय मानकों पर बहुत अधिक ध्यान दिए बिना समर्थन और खर्च बढ़ाने का समय है। इस बात का पूरा यकीन है कि आरबीआई और सरकार राजकोषीय दबावों के बावजूद प्रणाली में नकदी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।'' एसोचैम ने कहा कि सरकार और आरबीआई को 31 मार्च 2022 तक के लिए एक ब्याज सहायता योजना पर विचार करना चाहिए, खासकर सूक्ष्म और छोटे कारोबारियों के लिए। चैंबर ने सबसे बुरी तरह प्रभावित आतिथ्य क्षेत्र को राहत देने के लिए रेस्त्राओं को जीएसटी इनपुट क्रेडिट की अनुमति देने का सुझाव भी दिया। इसके अलावा रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्टांप शुल्क और संपत्ति कर को कम से कम तीन साल के लिए आधा करने की सिफारिश भी की है।

निजी यूज के लिए ऑक्सिजन कंसंट्रेटर खरीद रहे हैं, टैक्स में हुए इस बदलाव के बारे में जानिये

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना संकट के दूसरे चरण (2nd Wave of Corona) में देश में ऑक्सिजन की डिमांड (Demand of Oxygen) काफी बढ़ गई है। पिछले महीने तो हालत ऐसी रही कि बहुत से लोग ऑक्सिजन सिलेंडर (Oxygen Cylinder) लेने से उसे रिफिल करवाने या हॉस्पिटल में ऑक्सिजन सिलेंडर वाले बेड रिजर्व कराने के लिए सिफारिश तक लगाते हुए दिखे हैं। इस बीच बहुत से लोगों ने निजी उपयोग के लिए ऑक्सिजन कंसंट्रेटर (oxygen concentrator) आयात करने का भी फैसला किया।

अगर आप भी पर्सनल यूज़ के लिए ऑक्सिजन कंसंट्रेटर (oxygen concentrator) आयात कर रहे हैं या आपको विदेश से किसी ने ऑक्सिजन कंसंट्रेटर गिफ्ट में भेजा है तो आपको इस पर जीएसटी (GST) चुकाना पड़ेगा। पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि ऑक्सिजन कंसंट्रेटर (oxygen concentrator) के आयात या गिफ्ट में मिलने वाले ऑक्सिजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी (GST) नहीं चुकाया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे (Stay) लगा दिया है।

समानता के अधिकार का हनन

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 30 मई को आदेश दिया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए विदेश से ऑक्सिजन कंसंट्रेटर (oxygen concentrator) मंगाने पर आईजीएसटी (IGST) लगाना असंवैधानिक है। इस तरह के जरूरी उपकरणों पर टैक्स लगाने की वजह से समानता के अधिकार (right to equality) का हनन होता है। इसके बाद केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि ऑक्सिजन कंसंट्रेटर (oxygen concentrator) का सरकार द्वारा किया जाने वाला आयात जीएसटी (GST) से फ्री है और यह गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को फ्री दिया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने कहा कि निजी उपयोग के लिए अगर कोई व्यक्ति ऑक्सिजन कंसंट्रेटर (oxygen concentrator) का आयात कर रहा है तो उसकी तुलना गरीब और जरूरतमंद लोगों से नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और इसकी सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी।

मंत्रियों का ग्रुप लेगा फैसला

पिछले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह फैसला किया गया था कि कोविड-19 की वैक्सीन (Covid vaccine) और मेडिकल सप्लाई पर लगने वाले टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद मंत्रियों के समूह वाले 8 सदस्य का एक ग्रुप (GoM) बनाया गया था। इसमें अलग-अलग राज्यों के मंत्री शामिल हैं। यह ग्रुप इस बात पर फैसला करेगा कि कोरोना संकट के मद्देनजर किन चीजों की बिक्री या बंटवारे पर जीएसटी (GST) लगाया जा सकता है या किन चीजों पर जीएसटी की दरें कम की जा सकती है। मंत्रियों के समूह वाले इस ग्रुप की अध्यक्षता मेघालय के मुख्यमंत्री कोरंड संगमा कर रहे हैं। यह ग्रुप अपनी रिपोर्ट 8 जून को सौंपने जा रहा है।

कोविड-19 से प्रभावित इवेंट मैनेजमेंट उद्योग की प्रधानमंत्री से मदद की गुहार

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले 'इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मेनेजमेंट एसोसियेशन (ईईएमए) ने उद्योग की सहायता के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि कोविड-19 के कारण उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

संघ ने कहा है कि उसके 97 प्रतिशत सदस्य महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उन्हें कारोबार जारी रखने के लिए पूंजी या कर्ज की बहुत जरूरत है। ईईएमए ने कहा कि उसने 27 मई को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की हैं। इसमें कहा गया है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते पिछले एक साल से कार्यक्रम आयोजन से जुड़े इस उद्योग की कोई आय नहीं हुई हैं।

ईईएमए के अध्यक्ष रोशन अब्बास ने पीटीआई-भाषा से बुधवार को कहा, ''अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान हमारा काम पूरी तरह से बंद रहा और पिछले वर्ष नवम्बर से कुछ काम शुरू हुआ। लेकिन फरवरी 2021 के आते-आते हम एक बार फिर उसी स्थिति में पहुंच गए।''

उन्होंने कहा कि संघ के एक हजार से अधिक पंजीकृत सदस्य हैं, जिन्होंने पिछले अप्रैल से अपने कर्मचारियों की 50 से 80 प्रतिशत छंटनी की है। संगठन ने कहा, ''सभी बड़े कार्यक्रम अनिश्चित समय के लिए स्थगित या रद्द कर दिये गए हैं। इससे उद्योग की आय का 100 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। उद्योग से जुड़े एक करोड़ कर्मचारियों में 90 प्रतिशत दैनिक कर्मी है। कुल मिलाकर सभी कर्मचारी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।''

उद्योग निकाय ने सरकार से ईईएमए से जुड़े सदस्यों के सभी कर्मचारियों को एक वर्ष के वेतन का 50 प्रतिशत देने के साथ-साथ एक वर्ष के लिए सभी वैधानिक देनदारियों को स्थगित करने का आग्रह किया है। इसके अलावा अगले तीन वर्ष तक जीएसटी रिफंड, ऋण और ओवरड्राफ्ट पर दो साल की मोहलत और पूंजी ऋण की उपलब्धता को आसान बनाना तथा एक वर्ष के लिए ब्याज माफी समेत अन्य कई मांगे रखी है। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले इस उद्योग का कारोबार वित्त वर्ष 2020 में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये का था। कोविड महामारी से पहले एक करोड़ से अधिक लोगों को इसके जरिये रोजगार मिलता था, जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत प्रवासी थे।

मई में भारत रहा शुद्ध आयातक, इतने अरब डॉलर पर पहुंचा व्यापार घाटा

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत का निर्यात (Export) मई 2021 में 67.39 प्रतिशत बढ़कर 32.21 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। यह बात सरकार द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों से सामने आई है। वाणिज्य मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान इंजीनियरिंग, दवा, पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों के निर्यात में खासतौर से तेजी देखी गई। पिछले साल मई में निर्यात 19.24 अरब अमेरिकी डॉलर और मई 2019 में 29.85 अरब अमेरिकी डॉलर था। बयान के मुताबिक मई 2021 में आयात (घ्स्ज्दू) 68.54 प्रतिशत बढ़कर 38.53 अरब डॉलर हो गया, जो मई 2020 में 22.86 अरब डॉलर और मई 2019 में 46.68 अरब डॉलर था।

व्यापार घाटा सालाना आधार पर 74% बढ़ा

मंत्रालय ने कहा, ''भारत इस तरह मई 2021 में 6.32 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे के साथ एक शुद्ध आयातक है। मई 2020 में व्यापार घाटा 3.62 अरब डॉलर था। व्यापार घाटे में मई 2020 के मुकाबले 74.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई।''

तेल आयात बढ़कर पहुंचा 9.45 अरब डॉलर पर

समीक्षाधीन महीने में तेल आयात बढ़कर 9.45 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि मई 2020 में यह 3.57 अरब अमेरिकी डॉलर था। इस साल अप्रैल-मई के दौरान निर्यात बढ़कर 62.84 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 29.6 अरब डॉलर और अप्रैल-मई 2019 में 55.88 अरब डॉलर था

बाजारों में कार्यरत कर्मचारियों की परेशानियों का निकालेंगे हल

2 महीने का आर्थिक भत्ता जारी किया जावे

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सराफा व्यवसायी संतोष वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर सराफा बाजार अनलॉक के बाद भी संक्रमण न फैले इसलिए बंद रखा गया है पिछले 2 महीनों में अनेक बंगाली कारीगर एवं विभिन्न दुकानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को आ रहे आर्थिक संकट के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रदेश सरकार को भेजी जा रही है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन किया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर 2 महीने हेतु आर्थिक भत्ता जारी किया जावे। प्रदेश सरकार को प्रेषित से गए पत्र में संतोष वाधवानी लें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आवेदन देकर निजी दुकानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु भी सरकार को संवेदनशील होकर उनके लिए योजना बनाने का आग्रह किया है।

मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बताया खतरा, क्या वास्तव में इकोनॉमी का संकट बढ़ने वाला है?

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस (Moody's Investors Service) का मानना है कि भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (sovereign credit) के लिए खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह कोरोना की दूसरी लहर (second wave of corona) है। क्या वाकई यह भारतीय अर्थव्यवस्था (indian economy) का संकट बढ़ने का संकेत है? आखिर भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के लिए खतरा बढ़ने का क्या मतलब है? आइए इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं।

कोरोना की दूसरी लहर का कितना असर?

मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने भारत को लेकर मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते इकोनॉमिक रिकवरी (economic recovery) को झटका लगेगा, सरकार की वित्तीय सेहत (financial health) में गिरावट आएगी और देश के वित्तीय सेक्टर (financial sector) के लिए जोखिम बढ़ जाएगा। देश के वित्तीय सेक्टर के तहत बैंक (bank) और एनबीएफसी (NBFC) जैसे संस्थान आते हैं, जो उद्योग, कारोबार और आम आदमी की कर्ज की जरूरतें पूरी करते हैं।

क्रेडिट रेटिंग घटने से क्या होगा?

करीब एक साल पहले मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को निगेटिव

आउटलुक (Negative outlook) के साथ घटाकर बीएए3 कर दी थी। भारत की रेटिंग में और गिरावट आने से अर्थव्यवस्था (economy) के लिए संकट बढ़ जाएगा। जानकारों का मानना है कि इससे भारत में आने वाले विदेशी निवेश (इदीगुह ग्हनूसहू) पर खराब असर पड़ेगा। संस्थागत निवेशक सॉवरेन रेटिंग के आधार पर निवेश के फैसले लेते हैं। सॉवरेट रेटिंग घटने पर वे अपना निवेश निकालना पसंद करते हैं।

क्या सरकार की वित्तीय सेहत और बिगड़ेगी?

कोरोना की दूसरी लहर का आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा है। अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन (lockdown) के चलते आर्थिक गतिविधियां (economic activities) करीब ठप रही हैं। इससे सरकार के राजस्व (revenue) में बड़ी गिरावट आने की आशंका है। उधर, कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं (Health services) पर खर्च बढ़ाना पड़ा है। इससे स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में तय रकम से ज्यादा रहेगा।

वित्तीय सेक्टर में जोखिम बढ़ने का असर क्या होगा?

वित्तीय सेक्टर के लिए जोखिम (risk) बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। वित्तीय सेक्टर किसी अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन की तरह है। वित्तीय सेक्टर में संकट का मतलब है अर्थव्यवस्था में कर्ज की कम उपलब्धता। इसका सीधा असर आर्थिक ग्रोथ (economic growth) पर पड़ता है। नए निवेश के लिए वित्तीय संस्थाओं से कर्ज का प्रवाह जरूरी है। संकट में फंसा वित्तीय सेक्टर कर्ज देने से परहेज करता है। इससे रोजगार के नए अवसर (employment opportunities) पैदा करने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। साथ ही मांग में वृद्धि उम्मीद से कम रहती है।

आत्मनिर्भर, डिजिटल भारत के लिये कृषि महत्वपूर्णः तोमर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि कृषि क्षेत्र को साथ लेकर ही आत्मनिर्भर और डिजिटल भारत का सपना साकार हो सकेगा। मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिये ठोस कदम उठाये हैं। आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह बात कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ चार संस्थानों के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान कही। ये संस्थान है- पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस), ईएसआरआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं एग्रीबाजार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन संगठनों के साथ एक वर्ष की अवधि के भीतर आधार के रूप में किसान डेटाबेस का उपयोग करके पायलट परियोजना के लिए एमओयू किया गया है। बयान के अनुसार 'नेशनल एग्रीकल्चर जियो हब' की स्थापना तथा शुरूआत के लिये ईएसआरआई के साथ एमओयू किया गया है। वहीं अमेजन वेब सर्विसेज के साथ कृषि मूल्य श्रृंखला में डिजिटल सेवाओं और डिजिटल कृषि से संबंधित नवप्रवर्तन परिवेश के सृजन के लिए समझौता किया गया है। इसके अलावा डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए तीन राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान) में पायलट परियोजना के लिए कृषि विभाग के साथ सहयोग करने को लेकर एग्रीबाजार के साथ समझौता किया गया है। साथ ही तीन जिलों...हरिद्वार (उत्तराखंड), हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) और मुरैना (मध्य प्रदेश) में कृषि प्रबंधन और किसान सेवा के लिए पतंजलि के साथ एमओयू हुआ है।

आठ बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में अप्रैल में 56.1 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली। एजेंसी

आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अप्रैल 2021 में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 56.1 प्रतिशत बढ़ा। वृद्धि दर में आया बड़ा उछाल तुलनात्मक वार्षिक आधार निम्न होने तथा प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ने, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात और बिजली क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़े में यह जानकारी दी गयी। इससे पहले, अप्रैल 2020 में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के आठ बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 37.9 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। इसका कारण कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये देश भर में लगाया गया 'लॉकडाउन' था।

इस साल मार्च में आठ बुनियादी

उद्योगों की वृद्धि दर 11.4 प्रतिशत थी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''अप्रैल 2021 में यह उच्च वृद्धि दर काफी हद तक अप्रैल 2020 में निम्न तुलनात्मक आधार प्रभाव के कारण है। पिछले साल कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन तेजी से घटा था।'' वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 में प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, इस्पात, सीमेंट और बिजली उत्पादन में क्रमशः 25 प्रतिशत, 30.9 प्रतिशत, 400 प्रतिशत, 548.8 प्रतिशत और 38.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अप्रैल 2020 में इनमें क्रमशः 19.9 प्रतिशत, 24.2 प्रतिशत, 82.8 प्रतिशत, 85.2 प्रतिशत और 22.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी थी।

बयान के मुताबिक समीक्षाधीन माह के दौरान कोयला और उर्वरक खंड में भी वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, कच्चे तेल का उत्पादन अप्रैल में 2.1 प्रतिशत गिरा जबकि पिछले इसी माह में यह 6.4 प्रतिशत घटा था। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदित नायर ने कहा कि उम्मीद के अनुरूप राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण निम्न तुलनात्मक आधार से बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर तेज रही। उन्होंने कहा, ''सीमेंट और स्टील उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि के साथ सुधार काफी व्यापक है। हालांकि दोनों की वृद्धि दर हमारे अनुमान से कम है। इसका कारण संभवतः स्थानीय स्तर पर लगाये गये 'लॉकडाउन' का प्रभाव लगता है।'' नायर ने कहा, ''हमारा अनुमान है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में अप्रैल 2021 में 130 से 150 प्रतिशत वृद्धि होगी। उसके बाद मई 2021 में विभिन्न राज्यों में लगाये गये 'लॉकडाउन' और अन्य पाबंदियों से इसमें कुछ नरमी आ सकती है। आईआईपी में इन आठ बुनियादी उद्योग का भारांश 40.27 प्रतिशत है।

नीदरलैंड ने भारत से पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक हटाई, लेकिन क्वारंटीन में रहना होगा 10 दिन

नई दिल्ली। एजेंसी

इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए अच्छी खबर है। यूरोपीय देश नीदरलैंड (Netherlands) ने भारत से पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगी रोक मंगलवार 1 जून से हटा दी है। लेकिन वहां जाने से पहले यात्रियों को कोरोना टेस्ट (Corona test) कराना होगा और निगेटिव होने आने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही यात्रियों की वहां पहुंचने पर क्वारंटीन के नियमों को मानना होगा। भारत के साथ-साथ दक्षिण अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अफ्रीका की पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक हटा दी है। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के विकराल होने के कारण नीदरलैंड ने 26 अप्रैल को भारत से आने वाली पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। दिल्ली में नीदरलैंड की एंबेसी ने ट्वीट किया था कि भारत से पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगी रोक को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। भारत के साथ-साथ दक्षिण अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अफ्रीका की पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई थी।

10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा

नीदरलैंड ने भारत सहित इन देशों से आने वाली पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक हटा दी है लेकिन इन देशों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके मुताबिक इन देशों से आने वाले यात्रियों को 10 दिन तक अपनी पसंद की जगह में क्वारंटीन रहना होगा। अगर 5 दिन के बाद पैसेंजर कोरोना निगेटिव पाया जाता है तो उसका क्वारंटीन पीरियड 5 दिन में ही खत्म हो सकता है। अर्जेंटीना, बहरीन, ब्राजील, भारत और साउथ अफ्रीका जैसे हाई-रिस्क देशों से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य होगा।

किराए पर घर लेना और देना होगा आसान
मॉडल टेनेंसी एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मॉडल किरायेदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी। मॉडल किरायेदारी अधिनियम (model tenancy act) का मसौदा अब राज्यों (states) एवं केंद्र शासित प्रदेशों (union territories) को भेजा जायेगा। इसे नया कानून बनाकर या वर्तमान किरायेदार कानून में उपयुक्त संशोधन करके लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (central cabinet) की बैठक में इस मसौदे को मंजूरी दी गई ।

हाउसिंग सेक्टर के विकास को मिलेगा बढ़ावा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मॉडल किरायेदारी अधिनियम लाने का ऐलान किया था। बुधवार को सरकार ने कहा है कि इससे देशभर में किराये पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे (legal framework) को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे इस क्षेत्र के विकास का रास्ता खुलेगा। इसमें कहा गया है कि मॉडल किरायेदारी अधिनियम का (model tenancy act) मकसद देश में एक विविधतापूर्ण, टिकाऊ और समावेशी किराये के लिये आवासीय बाजार सृजित करना है।

बेघर लोगों को घर मिलेगा

मॉडल किरायेदारी अधिनियम के लागू होने पर हर आय वर्ग के लोगों के लिये पर्याप्त संख्या में किराये के लिये आवासीय इकाईयों का भंडार बनाने में मदद मिलेगी और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। इससे खाली पड़े घरों को किराये पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

हाउसिंग सेक्टर में निजी हिस्सेदारी बढ़ेगी

सरकार को उम्मीद है कि इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके। मॉडल किरायेदारी अधिनियम से आवासीय किराया व्यवस्था को संस्थागत रूप देने में मदद मिलेगी ।

देश में घरों की कमी दूर करने में मिलेगी मदद

मॉडल टेनेंस एक्ट से रेंटल हाउसिंग के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इससे देश में घरों की कमी की दूर करने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस एक्ट से शहरी और ग्रामीण प्रॉपर्टी के लिए एक मॉडल मिलेगा।

मकानमालिक और किराएदार के बीच विवाद घटेगा

सरकार का मानना है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट से मकानमालिक और किरायदारों के बीच विवाद में भी कमी आएगी। अभी विवाद की आंशका के चलते कई मकानमालिक घर खाली होने के बावूजद किराए पर देने से कतराते हैं।

महामारी में सब चाहे अपना वाहन, सेकेंड हैंड वाहनों की बिक्री में 250 फीसदी का उछाल

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना की दूसरी लहर से डरे लोग अब अपना वाहन (Self Owned Vehicle) खरीदने पर ज्यादा जोर देने लगे हैं। जिनके पास नई कार (New Car) या बाइक (New Bike) खरीदने को पैसे नहीं हैं, वे सेकेंड हैंड (Second hand car) भी लेने को तैयार हैं। स्थिति यह है कि सेकेंड हैंड वाहन बेचने वाले पोर्टलों का कारोबार पहले से न सिर्फ बढ़ गया है, बल्कि इन पर वाहन भी पहले ज्यादा बिक रहे हैं। इन पर सेकेंड हैंड वाहनों की बिक्री (Sale of Second hand vehicle) में 250 फीसदी का उछाल आया है।

सब चाहे अपना वाहन

ऑनलाइन ऑटोमोबाइल बेचने वाला प्लेटफार्म ड्रूम (Droom) के संस्थापक और सीईओ संदीप अग्रवाल का कहना है कि खुद के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के लिए प्राथमिकता में इस समय काफी तेजी आई है। ऐसी तेजी का कारण मुख्य रूप से महामारी के बीच बढ़ती सुरक्षा चिंता है। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसलटिंग फर्म बीसीजी (Boston Consulting Group) के अनुसार, कार से चलने वालो 70 फीसदी लोग अब अपनी स्वामित्व वाली कार में

चलना पसंद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोरोना महामारी के बीच वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transport) से बच कर ही रहें।

प्री कोविड से पोस्ट कोविड में बढ़ गया कारोबार

अग्रवाल का कहना है कि पिछले साल का फरवरी उनके कारोबार के लिए सबसे अच्छा महीना था। उस समय ड्रूम के ग्रॉस मोनेटाइजिंग वैल्यू (GMV) करीब 92 मिलियन तक पहुंचा था। यह जुलाई 2020 से फिर बढ़ना शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में लगभग 95 मिलियन तक पहुंच गया।

डिजिटल कारोबार में 250 फीसदी की तेजी

कोविड-19 (Covid-19) महामारी से ऑटोमोबाइल बाजार में भी एक नया चलन दिखने लगा है। अब लोग डिजिटल ऑटोमोबाइल कारोबार को तेजी से अपना रहे हैं। यही नहीं, नई कारों की तुलना में पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में तेज बढ़ोतरी हुई है। अग्रवाल बताते हैं कि प्री कोविड पीरियड में वह हर महीने लगभग 3000-4000 वाहन बेच पाते थे। अब यह बढ़ कर 7,500-10,000 वाहन प्रति माह बेचते हैं। इनमें 75 फीसदी हिस्सेदारी कारों की है जबकि 25 फीसदी हिस्सेदारी दोपहिया वाहनों की है।

हर एक नई कार पर बिकती हैं 1.65 गुना ज्यादा पुरानी कारें

ड्रूम के अध्ययन के मुताबिक इस समय देश भर में हर नई कार के लिए 1.65x पुरानी कारें बिकती हैं। इसका अनुमान है कि अगले दो से तीन वर्षों में यह अनुपात 2.5 गुना हो जाएगा।

क्या पसंद कर रहे हैं लोग

ड्रूम के अध्ययन के मुताबिक लोग इस समय लोग दो पहिया वाहनों में होंडा, बजाज और रॉयल एनफील्ड के वाहन ज्यादा खोजते हैं। जहां तक फोरव्हीलर की बात है तो इस सेगमेंट में मारुति, हुंडई और महिंद्रा के विभिन्न वेरिएंट के लिए बड़ी संख्या में पूछताछ हो रही है।

जीडीपी में 7.3% गिरावट पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा-आगे इकोनॉमी पर कोरोना का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यन ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का देश की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सोमवार शाम सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के जीडीपी के आंकड़े जारी किए। पिछले वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी में 7.3 फीसदी गिरावट आई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यन ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर कोरोना की दूसरी लहर का ज्यादा असर पड़ने के आसार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मार्च में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कोरोना की महामारी के पहले के स्तर पर आ गया है। ग्रामीण इलाकों में भी मांग में अच्छी तेजी देखने को मिली है। जीडीपी के आंकड़ों पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए सुब्रमण्यन ने कहा कि कोरोना की महामारी के चलते डिजिटल पेमेंट में 200 फीसदी से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वित्त वर्ष वर्ष के दौरान ग्रॉस वैल्यू एडेड में आया बदलाव ज्यादा अहम है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीवीए में 6.3 फीसदी की गिरावट आई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि इस साल देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस साल देश में सामान्य मानसून की उम्मीद जताई है। इससे फसल को मदद मिलेगी। पिछले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन पिछले चार दशक में सबसे खराब रहा है।

FY21 में राजकोषीय घाटा 18.21 लाख करोड़ रुपये, GDP का रहा इतने फीसदी

हालांकि, पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी में 8 फीसदी की गिरावट का अनुमान जताया गया था। इस तरह असल गिरावट अनुमान के मुकाबले कम है। जीडीपी के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि दिसंबर तिमाही में घरेलू अर्थव्यवस्था ग्रोथ (growth) में लौट आई थी।

रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा उसके आभासी मुद्रा संबंधी सर्कुलर को निरस्त मानें

मुंबई। एजेंसी

रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भुगतान प्रणाली भागीदारों से कहा है कि वह उसके अप्रैल 2018 में आभासी मुद्रा के बारे में जारी सर्कुलर को निरस्त समझें और ग्राहकों को संदेश में उसका उल्लेख नहीं करें। इस सर्कुलर को बाद में उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आरबीआई का यह ताजा आदेश तब जारी किया गया जब कुछ बैंकों और उसके नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों ने इस सकुर्लर का संदर्भ देते हुये अपने ग्राहकों को आभासी मुद्राओं में लेनदेन करने से आगाह किया।

रिजर्व बैंक ने यह सर्कुलर 6 अप्रैल 2018 को जारी किया था। इसमें कहा गया था कि उसके नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों को आभासी मुद्राओं से संबंधित किसी भी तरह की सेवायें देने से प्रतिबंधित किया जाता है। इनमें आभासी मुद्राओं की खरीद फरोख्त से संबंधित खातों में आने जाने वाली राशि संबंधी सेवाओं पर भी रोक लगाने को कहा गया था।

रिजर्व बैंक ने इस संबंध में सोमवार को कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों के जरिये उसके संज्ञान में आया है कि कुछ बैंक और नियमन इकाइयां अपने ग्राहकों को 6 अप्रैल 2018 को जारी सर्कुलर का संदर्भ देते हुये आभासी मुद्रा में लेनदेन से आगाह कर रहे हैं।

केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि इस सर्कुलर को 04 मार्च 2020 को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। ''माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुये यह सर्कुलर उच्चतम न्यायालय के फैसले के दिन से वैध नहीं रह गया है, इसलिये इसका संदेशों में जिक्र अथवा संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिये।'' रिजर्व बैंक ने यह सर्कुलर सोमवार को सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों, भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों, गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भुगतान प्रणाली भागीदारों के नाम जारी किया। रिजर्व बैंक ने कहा, हालांकि, बैंक मानक संचालन नियमनों के तहत अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी), मनी लांड्रिंग रोधी, आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) और मनी लांड्रिग रोधी कानून के तहत नियमन में आने वाली इकाइयों के दायित्व के तहत ग्राहकों की जांच परख प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं।

ज्येष्ठ मास 24 जून तक

ज्येष्ठ मास हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना होता है। ये 24 जून तक रहेगा। धर्मग्रंथों में इस महीने व्रत, पूजा-पाठ और दान का बहुत महत्व बताया गया है। ऋषि-मुनियों ने पर्यावरण को बचाने के लिए इस महीने खास व्रत-त्योहारों की व्यवस्था की गई है। इसलिए ज्येष्ठ महीने के दौरान आने वाले व्रत और त्योहारों में पानी और पेड़-पौधों की पूजा खासतौर से की जाती है।

इसी महीने में हुआ था शनिदेव का जन्म और श्रीराम-हनुमान की मुलाकात

ज्योतिषीय नजरिया

इस महीने में पूर्णिमा तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। इसलिए इसका नाम ज्येष्ठ पड़ा। इस महीने उत्तराषाढ़ा और पुष्य नक्षत्र को शून्य माना जाता है। यानी इनमें किए गए कामों में असफलता मिलती है और धन हानि भी होती है। साथ ही कृष्णपक्ष की चतुर्दशी और शुक्लपक्ष की त्रयोदशी तिथियों को भी शून्य तिथियां माना गया है। इन दिनों में शुभ काम नहीं करने चाहिए।

धर्मग्रंथों में खास

महाभारत में कहा गया है कि इस महीने नियम से रहकर एक समय भोजन करना चाहिए। इससे एश्वर्य बढ़ता है। शिवपुराण के मुताबिक ज्येष्ठ महीने में तिल का दान करने से शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं और सेहत अच्छी रहती है। इस महीने तिल के दान से शक्ति और उम्र भी बढ़ती है। वहीं, धर्मसिंधु ग्रंथ का कहना है कि इस महीने की पूर्णिमा पर तिल से हवन करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।

ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि इस महीने के कृष्णपक्ष की आखिरी तिथि यानी अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ था। इसलिए इस तिथि पर शनि जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा बताया गया है कि ज्येष्ठ महीने में ही हनुमान जी और श्रीराम की पहली मुलाकात हुई थी। इसलिए इस महीने के हर मंगलवार को श्रीराम और हनुमानजी की पूजा की जाती है। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में इस महीने की दशमी तिथि पर ही हनुमान जयंती मनाई जाती है।

संस्कृत में ज्येष्ठ यानी अन्य महीनों में बड़ा

पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉ. गणेश मिश्र बताते हैं कि प्राचीन काल गणना के मुताबिक हिंदू कैलेंडर के इस महीने में दिन बड़े होते हैं और इसे अन्य महीनों से बड़ा माना गया है। जिसे संस्कृत में ज्येष्ठ कहा जाता है। इसलिए इसका नाम ज्येष्ठ हुआ। इस महीने का स्वामी मंगल होता है। इसके आखिरी दिन पूर्णिमा तिथि के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र का संयोग बनता है। इसलिए भी इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है।

मंगल करेंगे अपने से नीच राशि में प्रवेश

वृषभ, मिथुन, तुला, धनु, कुंभ के जातकों का बदलेगा भाग्य, इन्हें रहना होगा सावधान

मंगल ग्रह का रंग लाल होता है जिसे शक्ति व आत्मबल का प्रतीक माना गया है. ऐसी मान्यता है कि जिसके कुंडली में मंगल उच्च कोटि का होता है. उसका आत्मविश्वास भी सदैव उच्च रहता है. आपको बता दें कि जून महीने में कई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं. ऐसे में 2 जून को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है. आइये जानते हैं सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा... जून माह का पहला मंगल गोचर सुबह 7 बजकर 17 मिनट पर अपने से नीच राशि कर्क में होगा. जिसका शुभ व अशुभ प्रभाव कई राशियों पर पड़ने वाला है.

मेष राशिः कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां उठानी पड़ सकती है. शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. यात्रा करने से बचें, दुर्घटना होने की आशंका है. इस दौरान जीवन साथी के साथ मनमुटाव भी हो सकता है.

वृषभ राशिः आपका समय ठीक रहेगा. कैरियर और व्यापार में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. हालांकि, जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

मिथुन राशिः धन आगमन के नये श्रोत खुलेंगे. किसी वाद विवाद में पड़ने की भी संभावना बन रही है. प्रॉपर्टी को लेकर कोई बड़ी डील हो सकती है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा.

कर्क राशिः क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें, वरना बना हुआ काम बिगड़ सकता है. नई नौकरी मिलने की संभावना है. जॉब भी बदल सकते हैं. समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सिंह राशिः लेन-देन के मामले में विशेष सावधान रहें. दांपत्य जीवन में कलह हो सकता है. यात्रा करने से बचें. वाहन दुर्घटना होने की संभावना है.

कन्या राशिः अटका हुआ धन वापस मिलेगा. किसी को कर्ज देने समय सतर्क रहें. पैसे डूबने की भी संभावना है. निवेश करने से पहले जांच परख ले. स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें.

तुला राशिः आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुताबिक सुधरेगी. नए अवसर मिल सकते हैं. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. घर में पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है.

वृश्चिक राशिः भाग्य आपका किसी भी कार्य में साथ नहीं देगा. आपको मेहनत करके ही फल प्राप्त करना होगा. इस दौरान आपको मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है. आर्थिक तंगी से भी परेशान रह सकते हैं.

धनु राशिः आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. आर्थिक रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे. किसी वाद विवाद में फंसने से बचें. धार्मिक कार्यों में रूची बढ़ेगी.

मकर राशिः दांपत्य जीवन में मनमुटाव होने की संभावना है. आलस्य के कारण आपके महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ सकते हैं. आर्थिक रूप से आप कमजोर महसूस करेंगे. मेहनत में विश्वास रखें भाग्य पर कम.

कुंभ राशिः आपके लिए समय लाभदायक होगा. धन अधिक खर्च करने से बचना होगा. कैरियर व्यापार में नए अवसर मिलेंगे हालांकि गुस्से पर कंट्रोल रखें

मीन राशिः आपकी आमदनी बढ़ सकती है. जॉब परिवर्तन का योग भी बन रहा है. परिवार के किसी सदस्य के साथ वाद विवाद हो सकता है.

कालाष्टमी व्रत 2 जून को: बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन भैरव पूजा और कुत्ते को खाना खिलाने की परंपरा

ग्रंथों के मुताबिक हर महीने कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कालाष्टमी मनाई जाती है।इस बार कालाष्टमी बुधवार 2 जून को है। इस दिन शिवजी के रुद्र स्वरूप भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काल भैरव के 8 स्वरूप माने गए हैं। इनमें से बटुक भैरव की पूजा गृहस्थ व अन्य सभी भैरव भक्तों द्वारा इस विशेष तिथि के मौके पर की जाती है, जो बेहद ही शुभफलदायी और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। बटुक भैरव स्वरूप को सौम्य स्वरूप माना गया है। काल भैरव के भक्त साल की सभी कालाष्टमी के दिन उनकी पूजा और उनके लिए उपवास करते हैं।

नारद पुराण में कालाष्टमी

नारद पुराण के मुताबिक कालाष्टमी पर काल भैरव और मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस रात देवी काली की भी विशेष पूजा का विधान है। शक्ति पूजा करने से काल भैरव की पूजा का पूरा फल मिलता है। इस दिन व्रत करने वाले को फलाहार ही करना चाहिए। इस व्रत के दिन कुत्ते को भोजन करवाना शुभ माना जाता है।

इस व्रत से दूर होते हैं रोग

कालाष्टमी पर्व शिवजी के रुद्र अवतार कालभैरव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कालाष्टमी व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि-विधान से काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं और काल उससे दूर हो जाता है। इसके अलावा व्यक्ति रोगों से दूर रहता है। साथ ही उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है।

कुत्ते को खाना खिलाने की परंपरा

भगवान भैरव का वाहन कुत्ता होता है, इसलिए इस दिन कुत्ते को पेटभर खाना खिलाने से विशेष फल मिलता है। ऐसा करने से भगवान भैरव खुश होते हैं और सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। माना जाता है कि कालाष्टमी के साथ ही हर दिन कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से बुरा समय दूर होता है और परेशानियां भी खत्म होने लगती हैं।

कालाष्टमी व्रत से खत्म होता है डर

मान्यता के मुताबिक, इस दिन व्रत और पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है और परेशानियां आने से पहले ही दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है। जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले होते हैं उनके लिए भगवान भैरव, दंडनायक होते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इनकी पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं।

हवन के दौरान क्यों किया जाता है स्वाहा शब्द का उच्चारण

सनातन धर्म के कई तरह के धार्मिक अनुष्ठानों आदि के बारे में बताया है। जिनमें हवन और यज्ञ का विशेष महत्व है। नया घर हो, नया बिजनेज या फिर शादी-ब्याह जैसा प्रत्येक कार्यक्रम में हवन व यज्ञ होता ही है। अक्सर आप ने देखा-सुना होगा कि हवन चाहे किसी भी पूर्ति के लिए किया जाए जब उसमें आहुतियां डाली जाती हैं तो 'स्वाहा' शब्द का उच्चारण किया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों हवन या यज्ञ आदि के दौरान 'स्वाहा' शब्द दोहराया जाता है? अगर नही तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इससे संबंधित कुछ खास जानकारी-

प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार असल में स्वाहा अग्नि देवी की पत्नी हैं। जिस कारण जब हवन के दौरान मंत्र जप के बाद इनके नाम का उच्चारण किया जाता है। कहा जाता है स्वाहा का अर्थ होता है सही रीति से पहुंचाना। तो आम भाषा में इसका मतलब जरूरी पदार्थ को उसके प्रिय तक सुरक्षित पहुंचाना होता है। धर्म शास्त्री बताते हैं कि श्रीमद्भागवत गीता व शिव पुराण में इनसे संबंधित काफी उल्लेख पढ़ने सुनने को मिलता है। इसमें किए वर्णन के अनुसार मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा कहकर हवन सामग्री भगवान को अर्पित किए जाने का विधान है।

शास्त्रों के अनुसार यज्ञ चाहे किसी भी तरह की मनोकामना आदि के लिए किया जाए, अगर उसे देवता ग्रहण न करें तो वह यज्ञ पूर्ण नही माना जाता। अब सवाल ये है कि देवता इसे ग्रहण करते कैसे हैं, तो आपको बता दें देवताओं तक हवन तब पहुंचता है, जब हवन में आहुति डालते समय स्वाहा शब्द उच्चारते हैं। जी हां, कहा जाता है अग्नि के द्वारा ही स्वाहा में माध्यम से हवन देवताओं को अर्पण किया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वैदिक ग्रंथों में अग्नि की महत्ता पर अनेक सूक्तों की रचनाएं हुई हैं।

इससे जुड़ी कथाओं के अनुसार, स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। जिनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। कहा जाता है अग्निदेव केवल अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हवन ग्रहण करते हैं तथा उनके माध्यम से यही हविष्य आह्वान किए गए देवता को प्राप्त होता है।

इससे जुड़ी अन्य अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक, पवमान और शुचि नामक तीन पुत्र हुए। स्वाहा की उत्पत्ति से एक और रोचक कहानी के अनुसार, स्वाहा प्रकृति की ही एक कला थी, जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह पर संपन्न हुआ था। भगवान श्रीकृष्ण ने स्वाहा को वरदान दिया था कि उन्हीं के माध्यम से देवता हविष्य को ग्रहण कर पाएंगे।

सेफ्टी टेस्टः 'देसी' कारों ने छुड़ाए विदेशी कंपनियों के छक्के, टॉप 5 पर भारत का कब्जा

नयी दिल्ली। एजेंसी

बीते कुछ वक्त में भारत में कार खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा कार बायर्स हैं। ऐसे में कार कंपनियां भी अब पहले के मुकाबले सेफ्टी पर भी खासा ध्यान देते हैं। उर्दीत ऊँइ ने भारत में सबसे सेफ कारों की लिस्ट जारी की है। आइए नजर डालते हैं टॉप 5 सेफेस्ट कारों पर।

Mahindra XUV300

महिंद्रा की फ्लैगशिप सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इस लिस्ट में पहले नंबर पर रही। इस कार को Global NCAP ने 'Safer Choice' अवॉर्ड दिया था। कार को अडल्ट ऑक्युपेंट सेफ्टी में 5 स्टार और चाइल्ड ऑक्युपेंट सेफ्टी में 4 स्टार मिले।

टाटा अल्ट्रॉज

Tata Altroz भारत की सबसे सेफ कारों में से एक है। इस को क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल हुई थी। टाटा की इस हैचबैक में हेड, नेक प्रटेक्शन के लिए अच्छा स्पेस दिया गया है।

Tata Nexon

यह टाटा की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इस लिस्ट में यह कार तीसरे नंबर पर है। कार को अडल्ट ऑक्युपेंट सेफ्टी में 4 स्टार और चाइल्ड ऑक्युपेंट सेफ्टी में 3 स्टार मिले थे। टेस्ट में कार के बॉडी शेल को स्टेबल बताया गया है।

महिंद्रा थार

Mahindra Thar कंपनी की ऑफरोडर एसयूवी है। इस लिस्ट में कार चौथा स्थान दिया गया है। कार क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिली थी। नवंबर 2020 में इस कार की टेस्टिंग की गई थी।

टाटा टिगोर

टाटा टिगोर भी सेफ कारों की लिस्ट में टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रही। इस कार को 4 स्टार अलडल्ट सेफ्टी के लिए और 3 स्टार चाइल्ड सेफ्टी के लिए 3 स्टार मिले थे।

पिछले छह वर्षों में दुग्ध उत्पादन 6.3 प्रतिशत सालाना की दर से बढा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत में दूध उत्पादन पिछले छह वर्षों के दौरान सालाना औसतन 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वह विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित 'ऑनलाइन' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने मवेशी और डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, गोपाल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की।

उन्होंने उल्लेख किया कि पात्र किसान, डेयरी सहकारी समितियां या एआई तकनीशियन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पुरस्कार के लिए पोर्टल 15 जुलाई 2021 से खुलेगा। पुरस्कार के लिए विजेताओं की घोषणा 31 अक्टूबर 2021 को की जाएगी। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि भारत ने वर्ष 2019-20 के दौरान 19.84 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया। उन्होंने कहा कि दूध के उत्पादन का मूल्य 2018-19 के दौरान मौजूदा कीमतों पर 7.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यह गेहूं और धान के कुल उत्पादन मूल्य से अधिक है।

सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि पिछले छह वर्षों के दौरान दुग्ध उत्पादन औसतन 6.3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है जबकि विश्व दुग्ध उत्पादन 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वर्ष 2013-14 में प्रति व्यक्ति 307 ग्राम से बढ़कर वर्ष 2019-2020 में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 406 ग्राम हो गई है। कार्यक्रम को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव कुमार बाल्यान और प्रताप चंद्र सारंगी ने भी संबोधित किया।

डेयरी उत्पाद निर्यातकों की समस्याओं को दूर करने के किये जा रहे हैं उपायः अधिकारी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार डेयरी उत्पाद निर्यातकों की समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठा रही है ताकि इस क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में संयुक्त सचिव वर्षा जोशी ने कहा कि डेयरी उद्यमियों को समर्थन देने के लिए एक निवेश प्रोत्साहन डेस्क भी स्थापित किया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जोशी के हवाले से एक बयान में कहा, "डेयरी क्षेत्र के निर्यातकों के सामने आने वाली दिक्कतों को दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं।" वह विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित एक वेबिनार में बोल रही थीं।

अमूल ब्रांड नाम से डेयरी उत्पाद बेचने वाले गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक, आर एस सोढ़ी ने चीन, यूरोपीय संघ, दक्षिण

अफ्रीका और मैक्सिको में निर्यात उत्पादों की बाजार पहुंच में आने वाली बाधाओं के बारे में जानकारी दी।

सोढ़ी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश (35 प्रतिशत) और पाकिस्तान (45 प्रतिशत) जैसे पड़ोसी देशों द्वारा लगाया जाने वाला उच्च आयात शुल्क भी निर्यातकों के लिए समस्या है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में सचिव अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि भारत दूध उत्पादन में आत्मानिर्भर है और निर्यात के लिए पर्याप्त उपलब्धता होती है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अध्यक्ष (अनुसंधान) राकेश मोहन जोशी के अनुसार, दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, भारत की विश्व डेयरी उत्पाद बाजार में महज 0.36 प्रतिशत की हिस्सेदारी है जो कि बहुत कम है। जोशी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उपभोक्ता है जिसकी वजह से डेयरी उत्पादों के सभी प्रमुख निर्यातक देश इस विशाल बाजार में प्रवेश के लिए उत्सुक रहते हैं।

बिजली की खपत मई में 8.2 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। एजेंसी

बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बिजली की खपत मई में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.2 प्रतिशत बढ़कर 110.47 अरब यूनिट (बीयू) हो गई। इससे बिजली की वाणिज्यिक और औद्योगिक मांग में धीमी गति से सुधार का संकेत मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मई में बिजली की औद्योगिक मांग में सुधार की धीमी गति के लिए महामारी की दूसरी लहर के बीच राज्यों द्वारा लगाए गए स्थानीय लॉकडाउन प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मई में देश के पूर्वी और पश्चिमी तट पर आए दो चक्रवातों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में बारिश और तापमान में कमी के कारण भी बिजली की खपत कम हुई। पिछले साल मई में बिजली की खपत 102.08 बीयू थी और इसमें मई 2020 के मुकाबले 15 प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी। मई 2019 में बिजली की खपत 120.02 बीयू थी।

महामारी की दूसरी लहर की मार, मई में सभी कंपनियों की कार बिक्री में भारी गिरावट

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश की प्रमुख वाहन कंपनियों मसलन मारुति सुजुकी, हुंदै, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और टोयोटा किर्लोस्कर की वाहन बिक्री में मई महीने में अप्रैल के मुकाबले बड़ी गिरावट दर्ज हुई। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच विभिन्न राज्यों में लगाये गये लॉकडाउन की वजह से इन कंपनियों का उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हुई। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने औद्योगिक इस्तेमाल की ऑक्सीजन को चिकित्सा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक से 16 मई तक अपना उत्पादन बंद रखा। मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की कुल बिक्री अप्रैल के मुकाबले मई में 71 प्रतिशत घटकर 46,555 इकाई रह गई। अप्रैल में कंपनी ने 1,59,691 वाहन बेचे थे। कंपनी ने कहा कि मई में घरेलू बाजार में डीलरों को उसकी आपूर्ति 75 प्रतिशत घटकर 35,293 इकाई रह गई, जो इससे पिछले महीने 1,42,454 इकाई रही थी।

माह के दौरान कंपनी की मिनी कारों... आल्टो और एस-प्रेसो की बिक्री 81 प्रतिशत घटकर 4,760 इकाई रह गई। अप्रैल में यह आंकड़ा 25,041 इकाई रहा था। कॉम्पैक्ट खंड में... स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर की बिक्री 72 प्रतिशत घटकर 20,343 इकाई रही जो अप्रैल में 72,318 इकाई रही थी। मध्यम आकार की सेडान सियाज की बिक्री घटकर 349 इकाई रह गई। अप्रैल में यह 1,567 इकाई रही थी।

कंपनी के यूटिलिटी वाहनों विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस और एर्टिगा की बिक्री 75 प्रतिशत घटकर 6,355 इकाई रह गई, जो एक महीने पहले 25,484 इकाई रही थी। मई में कंपनी का निर्यात 35 प्रतिशत घटकर 11,262 इकाई रह गया। अप्रैल में कंपनी ने 17,237 वाहनों का निर्यात किया था। मारुति की प्रतिद्वंद्वी हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) की घरेलू बाजार में बिक्री 49 प्रतिशत घटकर 25,001 इकाई रह गई, जो अप्रैल 2021 में 49,002 इकाई थी। कंपनी ने बताया कि विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू प्रतिबंधों के कारण डीलरों को गाड़ियां भेजने में बाधा आई। अन्य प्रमुख घरेलू वाहन कंपनी टाटा मोटर्स की यात्री वाहनों की घरेलू बाजार में बिक्री 40 प्रतिशत घटकर 15,181 वाहनों की रही, जो अप्रैल में 25,095 इकाई रही थी। इसी तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा की घरेलू यात्री वाहन बिक्री मई में 56 प्रतिशत घटकर 8,004 इकाई रह गई, जो अप्रैल 2021 में 18,285 इकाई रही थी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की बिक्री मई में 707 इकाई रही। अप्रैल में कंपनी की बिक्री 9,622 इकाई रही थी। पिछले साल मई में कंपनी ने 1,639 वाहन बेचे थे।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन सोनी ने एक बयान में कहा, "पिछले महीने बिदाडी के हमारे कारखाने में कोई उत्पादन नहीं हुआ। देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन और जरूरी प्रतिबंधों के चलते बिक्री कारोबार भी काफी कम रहा। ऐसे में पिछले महीने (मई 2021) के आंकड़ों को एक साल पहले मई के आंकड़ों के साथ तुलना करना ज्यादती होगी। मई 2020 में परिचालन और बिक्री दोनों ही धीरे धीरे शुरू हो गये थे। होंडा कार्स इंडिया लि. ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के बीच मई में घरेलू बाजार में 2,032 वाहन बेचे। एक अन्य कार कंपनी एमजी मोटर इंडिया की बिक्री मई में 1,016 इकाई रही। कंपनियों का कहना है कि कोराना वायरस की दूसरी लहर के प्रभाव को रोकने के लिये विभिन्न राज्यों में लगाये गये लॉकडाउन का कारोबार पर असर रहा। कारखानों में इस्तेमाल होने वाली आक्सीजीन को भी चिकित्सा उपयोग के लिये दिया गया।

कोरोना से लड़ने में होगी आसानीः डेढ़ लाख रुपये में आता था पीएपीआर किट, देश में बनाया 30 हजार रुपये में

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना महामारी से जूझ रहे मरीजों की सेवा में लगे फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए अच्छी खबर है। अमृता विश्व विद्यापीठम के अकादमिक और अनुसंधान केंद्र ने अम्माची लैब्स के सहयोग से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बेहद किफायती किट डिजाइन और विकसित किए हैं। देश में पहली बार बनाए गए ये पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर (PAPR) किट अमृता अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

इसे भारत को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक और कदम भी कहा जा सकता है। हाल तक, देश में सभी पीएपीआर आयात किए जाते थे और इनकी कीमत एक लाख रुपये से अधिक थी। महामारी के दौरान समस्या गंभीर होने के साथ, सुरक्षा उपकरणों को उपलब्ध कराने के मामले में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अमृता हॉस्पिटल्स और अम्माची लैब्स ने इस साल जनवरी में संयुक्त रूप से पीएपीआर उत्पाद लॉन्च किया।

क्या होता है पीएपीआर

पीएपीआर एक सुरक्षा उपकरण तकनीक है, जिसका उपयोग कोविड वार्ड जैसे संक्रमण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सा कर्मियों को शुद्ध हवा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। ये स्वास्थ्य कर्मियों को एरोसोलाइज्ड वायरस कणों से संक्रमण और बीमारी से बचाने में बेहद महत्वपूर्ण हैं। पीएपीआर आमतौर पर एन95 मास्क वाले सामान्य पीपीई की तुलना में इस्तेमाल में अधिक सुरक्षित, अधिक आरामदायक होते हैं और इनका पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अत्यधिक महंगा होने के कारण, भारत जैसे विकासशील देशों में उनका व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है।

अम्माची लैब्स के निदेशक डॉ. भवानी राव आर ने कहा, 'इस प्रोडक्ट को कई अमृता संस्थानों के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और इंजीनियरों ने मिलकर विकसित किया है। पीएपीआर में न केवल चिकित्सा क्षेत्र के बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की मदद करने की क्षमता है, जिससे समाज पर एक ठोस प्रभाव पड़ता है। एक बार सभी फीडबैक और डिज़ाइन सुधारों को शामिल करने के बाद ओमनेक्स इंक इसकी उत्पादन और मार्केटिंग करेगी। वाणिज्यिक पीएपीआर की कीमत कहीं भी 70,000-1,50,000 रुपये है जबकि हमारे पीएपीआर की कीमत 30,000 रुपये प्रति किट से कम होगी।'

शराब की होम डिलीवरी पर कंपनियों ने किया चीयर्स, लोग इंटरनेट पर ढूंढने लगे इसका ऐप!

नयी दिल्ली। एजेंसी

दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाजत क्या दी, तमाम ई-कॉमर्स और डिलीवरी कंपनियों (Ecommerce Companies Liquor Home Delivery) की आंखों में चमक आ गई है। कहना गलत नहीं होगा कि इस मौके पर ये कंपनियां दिल्ली सरकार के फैसले को चीयर्स कहती हुई दिख रही है। स्विगी, जोमैटो, ऐमजॉन, ग्रॉफर्स और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां अब उन संभावनाओं को तलाशने में जुट गई हैं, जिनसे वह शराब की होम डिलीवरी के दिल्ली सरकार (Delhi Govt Allows Liquor Home Delivery) के फैसले से मुनाफा कमा सकें। जहां एक ओर कंपनियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, वहीं लोग भी इंटरनेट पर दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी के ऐप (delhi liquor home delivery apps) और वेबसाइट ढूंढ रहे हैं।

बाकी राज्य भी चल सकते हैं दिल्ली सरकार के रास्ते पर

अभी दिल्ली सरकार के शराब की होम डिलीवरी के फैसले पर पूरी डीटेल्स आनी बाकी हैं, लेकिन शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और इसकी मार्केटिंग आदि से जुड़ी कंपनियां खुश हैं। वह मान रही हैं कि कोरोना की वजह से शराब के जिस बिजनस को तगड़ा झटका लगा था, उसे दिल्ली सरकार के इस फैसले को फिर से फलने-फूलने में मदद मिलेगी। कंपनियां इसलिए भी खुश हैं क्योंकि अभी जो फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है उसे धीरे-धीरे बाकी राज्य भी अपनाएंगे, क्योंकि शराब से राज्यों की काफी कमाई होती है।

ऐप और वेबसाइट के जरिए होम डिलीवरी की सुविधा

दिल्ली सरकार ने सोमवार को ही ये घोषणा की थी कि एक संशोधित एक्साइज नियम के तहत शराब की डिलीवरी मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए की जा सकेगी। दिल्ली शराब के बाजारों में सबसे बड़ा है। ई-कॉमर्स कंपनियों ने तो इसके लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का पता लगाना भी शुरू कर दिया है। द बीयर कैफे के फाउंडर राहुल सिंह कहते हैं कि इससे शराब का बिजनस तेजी से बढ़ेगा और बाकी राज्य भी इस ओर कदम बढ़ाएंगे।

कई राज्य पहले भी कर चुके हैं शराब की होम डिलीवरी की कोशिश

पिछले साल पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी शराब की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की थी। हालांकि, वह फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि स्विगी और जोमैटे जैसे एग्रिगेटर्स ने दिशा-निर्देशों को आभाव में भारी-भरकम फीस वसूलना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र और केरल ने भी ये शुरू किया था, लेकिन बहुत सारे स्थानीय प्रतिबंधों के साथ। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में यह प्रयोग कितना सफल होता है और अगर सफल होता है तो बाकी राज्य किया करते हैं।

जर्मनी ने बड़ी कंपनियों के लिये यूरोपीय संघ के कर पारदर्शिता समझौते का स्वागत किया

बर्लिन। एजेंसी

जर्मनी के वित्त मंत्री ओलाफ स्कोल्ज ने बुधवार को बड़ी कंपनियों के लिये कर की जानकारी देने से जुड़े समझौते का स्वागत किया है। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ में बड़ी कंपनियों को अब बताना होगा कि उन्होंने किस-किस देश को कितना-कितना कर दिया है। इस बारे में मंगलवार देर रात यूरोपीय संघ के 27 देशों के प्रतिनिधियों और यूरोपीय संसद के बीच समझौता हुआ। इस समझौते से जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां प्रभावित होंगी, उनमें गूगल और अमेजन शामिल हैं। ये कंपनियां कर का बोझ कम करने के लिये आयरलैंड और लक्जमबर्ग जैसे कम कर वाले देशों में इकाइयों के जरिये काम कर रही थी। वित्त मंत्री स्कोल्ज ने कहा, ''यह कर न्याय को लेकर एक बड़ा कदम है। यह नियम पारदर्शिता सृजित करेगा ताकि अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपनी कर बाध्यताओं से बच नहीं पाये। कर बचाने को लेकर जो चालबाजी की जा रही थी, उसे समाप्त करने की जरूरत है।'' यूरोपीय संघ का अनुमान है कि बड़ी कंपनियां कर से बचने के जो उपाय कर रही हैं, उससे हर साल ईयू को 50 अरब यूरो (61 अरब डॉलर) का नुकसान हो रहा है। समझौते को अभी औपचारिक रूप से अंतिम मंजूरी देना बाकी है।

गोयल ने उद्योग संघों से कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग संघों से कहा है कि वे कोविड-19 की तीसरी लहर आने की स्थिति में उससे निपटने के लिए तैयार रहे। उन्होंने उद्योग जगत को महामारी से प्रभावित बच्चों की मदद करने का भी सुझाव दिया। केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा करने के लिए उद्योग संघों के साथ एक जून को हुई बैठक में यह बात कही। गोयल ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण औद्योगिक उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि उद्योग संघों से यह उम्मीद है कि वे वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पिछले अनुभवों से सीखे गए सबक का लाभ उठाएंगे। बैठक में सीआईआई और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि शामिल थे।

कोविड-19 महामारीः कम मांग के चलते समुद्री उत्पादों का निर्यात घटा

कोच्चि। एजेंसी

कोविड-19 महामारी और विदेशी बाजारों में मांग घटने के चलते देश के समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात कारोबार में गिरावट का सामना करना पड़ा। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इस क्षेत्र का निर्यात मात्रा के लिहाज से 10.88 प्रतिशत घटकर 11,49,341 टन रह गया, जिसका कुल मूल्य 43,717.26 करोड़ रुपये (5.96 अरब डालर) रहा। इस तरह निर्यात में इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले रुपये की मद में 6.31 प्रतिशत की कमी हुई, हालांकि, पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें सुधार देखने को मिला। डालर के लिहाज से निर्यात कारोबार में 10.81 प्रतिशत की गिरावट रही। भारत ने 2019-20 में 46,662.85 करोड़ रुपये मूल्य के 12,89,651 टन समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात किया था। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के अध्यक्ष के एस श्रीनिवास ने कहा, ''महामारी ने पहली छमाही के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात को काफी प्रभावित किया, लेकिन 2020-21 की अंतिम तिमाही में इसमें अच्छा सुधार हुआ। इसके अलावा एक्वाकल्चर क्षेत्र ने इस वित्त वर्ष के दौरान निर्यातित वस्तुओं में डॉलर मद में 67.99 प्रतिशत और मात्रा के रूप में 46.45 प्रतिशत योगदान देकर बेहतर प्रदर्शन किया।''

समीक्षाधीन अवधि में अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ (ईयू) भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रमुख आयातक थे। समुद्री उत्पादों के निर्यात में झींगा मछली का सबसे अधिक योगदान रहा। ऐसे उत्पादों की निर्यात मात्रा में 51.36 प्रतिशत और डालर में हुई प्राप्ति में इनका 74.31 प्रतिशत योगदान रहा। अमेरिका इसका सबसे बड़ा आयातक देश रहा है। इसके बाद चीन, यूरोपीय संघ और जापान इसके आयातक देश रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व के देशों को भी इसका निर्यात किया गया।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।